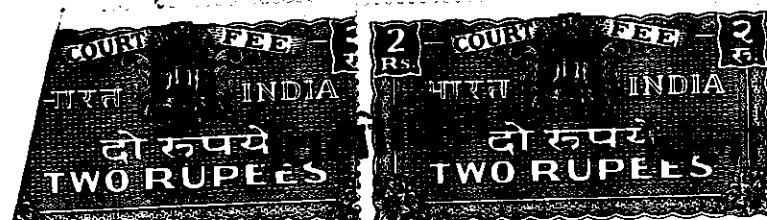


न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर  
प्रकरण कमांक ————— / 2003 पुनरीक्षण याचिका



पिता

C. F. Rs 15/-

पिता  
भिला-माला-कमला-

R-1069-II/2003

राजस्व द्वारा प्रकरण कमांक 266/2000-2001 अपील द्वारा पारित आदेश  
की एन. को २१/८१ द्वारा दिनांक ६-६-२००३ को प्रस्तुत  
द्वारा आज दि. १७/७/०३ को प्रस्तुत  
लाल संचित  
लाल संचित  
मध्य प्रदेश भूराजस्व सहिता १९५९।

महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण याचिका सादर निम्नप्रकार से प्रस्तुत

है।

#### प्रकरण के तथ्य ( Facts Of The Case )

- 1— यह कि आवेदक ने दिनांक 9-7-1976 को जर्ये रजिस्ट्री कमांक 1060 के द्वारा सुम्मा पत्नी अमर सिंह उर्फ उमय सिंह निवासी ग्राम वद्रबास परगना कोलारस जिला शिवपुरी से 4000/- रुपये मे ग्राम कदवाया परगना अशोक नगर ने सर्वे कमांक 268 रकवा 2.08 हेक्टर तथा सर्वे कमांक 320 रकवा 0.105 हेक्टर इस प्रकार कुल मिलाकर रकवा 2.133 हेक्टर क्य की थी।
- 2— यह कि न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 अशोक नगर प्रकरण कमांक ८०/८७ ई०दी मे भेरो विरुद्ध राम भरोसा आदि मे अन्तर्गत धारा ३९ नियम (1) तथा (2) का प्रस्तुत किया था जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 20-7-77 को निरस्त कर दिया गया।
- 3— यह कि भेरो तथा चिन्दूलाल आपस मे खास पिता पुत्र है। इस कारण से भी यह आदेश अनावेदक पर वाइन्डिंग होता है।
- 4— यह कि न्यायालय तेहसीलदार ईसागढ़ के समक्ष अनावेदक चिन्दू पुत्र भेरोलाल ने विवादित भूमि का कब्जा इन्द्राज वावत प्रस्तुत किया था जो भलत अधारो पर स्वीकार हुआ। इससे दुखित होकर आवेदक ने प्रथम अपील न्यायालय ई०डी०ओ० अशोक नगर के समक्ष प्रस्तुत की थी जिसका प्रकरण कमांक 158 अपील १५८/९९/२००० होकर दिनांक 24-2-2002 को न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई।
- 5— यह कि न्यायालय श्री एस०पी० गुप्ता अपर आयुक्त ग्वालियर के समक्ष अनावेदक ने प्रस्तुत की थी जो दिनांक ६-६-०३ को स्वीकार की गई।

( H. K. Soni )

✓

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

मांग — 3

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1069—दो / 2003

जिला अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकर्ता एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२। -12-2016	<p>आवेदक अभिभाषक श्री एम०पी० भटनागर एवं अनावेदक अभिभाषक श्री एस०के० श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 266 / 2000-01 / अपील में पारित आदेश दिनांक 06-6-2003 के विरुद्ध म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष कब्जे इन्द्राज हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार ने संहिता की धारा 32 की शक्ति का उपयोग करते हुये कब्जे का इन्द्राज करने का आदेश पारित किया है। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को अपर आयुक्त द्वारा भी उचित माना है। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह भी निष्कर्ष निकाला है कि गलत धारा के लिखने से प्रकरण गलत शीर्ष में दर्ज होता है तो इससे प्रकरण के तथ्य नहीं बदलते हैं और ऐसी तकनीकी त्रुटियों के आधार पर पक्षकार को सारभूत न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता। अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये निष्कर्ष में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p>  	(एस. एस. अली) सदस्य